Proposal to Finance Small Newspapers

8368. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government propose to finance the small papers especially language newspapers for establishment of printing presses and working capital;

(b) what are the details regarding the newspapers being financed or getting financial assistance, State-wise; and

(c) the procedure Government have adopted in this regard?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) No, Sir. However, at the instance of the Government it has been decided by the Industrial Development Bank of India to grant financial assistance to newspaper industries.

(b) and (c). Do not arise.

Award for the best Agriculture Programme by Upgrah Doordarshan, New Delhi

8369. SHRI M. A. HANNAN ALHAJ: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some prizes were distributed for the best agriculture programme done by Upgrah Doordarshan, New Delhi;

(b) whether one agriculture programme got award in Japan T.V. Competition held in 1977; and

(c) if so, the details thereof, the persons involved in production and those who were given the award?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c). Yes, Sir. The "Chaupal" programme produced by the Upgraha Doordarshan Kendra, New Delhi, won the 'Japan Prize' in a competition held in Tokyo in 1977. The prize money was US $500.1/3rd of the money was credited to Government and the remaining 2/3rd distributed to the following persons who were involved in the production of the programme:—

(i) Shri K. K. Chaturvedi, Producer.

(ii) Shri J. P. S. Arora, Assistant Engineer

(iii) Shri S. G. Sane, Film Editor.

(iv) Shri J. P. Gautam, Cameraman.

(v) Shri G. D. Shukul, Station Director (Script Writer).

आदिवासी किसानों द्वारा सिंचाई प्रयोजनों के लिए प्रयोग की गई बिजली पर मांग शुल्क और न्यूनतम शुल्क का समाप्त किया जाना

8370. श्री हीरा सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई प्रयोजनों के लिए आदिवासी किसानों द्वारा प्रयोग की गई बिजली पर वर्ष 1978-79 के दौरान लगाए गए मांग शुल्क और न्यूनतम शुल्क को समाप्त करने के लिए आदेश जारी किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो कितना शुल्क समाप्त किया गया है और किस तारीख से ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए आदिवासी क्षेत्रों के किसानों से इस वर्ष शत प्रतिशत मांग-शुल्क और न्यूनतम शुल्क वसूल किए गए थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त आदेश को रद्द करने के लिए कोई निर्णय किया है ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ङ). सप्लाई की शर्तें निर्धारित करने, मांग प्रभार तथा न्यूनतम प्रभार लगाने और समाप्त करने के अधिकार विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 49 के अन्तर्गत पूर्ण रूप से